

केनरा बैंक
बनाम
अजितकुमार जी.के.

(सिविल अपील क्रमांक 255/2025)

11 फ़रवरी 2025

(न्यायमूर्ति श्री दीपांकर दत्ता* एवं न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा)

विचारणीय बिंदु

प्रतिवादी के पिता की मृत्यु अपीलकर्ता की सेवा के दौरान हुई थी। अपीलकर्ता द्वारा 8 मई, 1993 के परिपत्र संख्या 154/93 में निहित अनुकम्पात्मक नियुक्ति की एक योजना उस समय लागू थी जब यह मृत्यु हुई। विचारणीय प्रश्न, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित थे: 1) क्या उच्च न्यायालय की खंडपीठ अपीलकर्ता की अंतःन्यायालयीय अपील को अनुमति न देकर और एकल न्यायाधीश के निर्णय को बरकरार रखते हुए, उस समय प्रतिवादी की अनुकंपा नियुक्ति का निर्देश देने में अनुचित थी जब वह 44 (चौवालीस) वर्ष की आयु पार कर चुका था; 2) क्या प्रतिवादी के पिता के निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए समय की चूक हुई थी; 3) क्या प्रतिवादी के पिता की मृत्यु के परिणामस्वरूप परिवार की वित्तीय स्थिति का उचित और तर्कसंगत आकलन किया गया था; और 4) क्या प्रतिवादी को आयु में छूट दी जानी चाहिए थी।

शीर्ष टिप्पणियाँ[†]

सेवा विधि – अनुकम्पा नियुक्ति – क्या समय का व्यतीत होना अनुकम्पात्मक नियुक्ति से इंकार करने का एक महत्वपूर्ण आधार है – क्या दावेदार की आयु एक निर्णायक कारक है?

अभिनिर्धारित: अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक यह है कि इसे शीघ्रतम दिया जाना चाहिए – जब तक कि कठिनाई कम करने की आवश्यकता उत्पन्न होने के तुरंत बाद नियुक्ति नहीं की जाती है, तब तक (i) मृतक कर्मचारी की अचानक समय से पहले और असामयिक मृत्यु या (ii) चिकित्सा अक्षमता जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी सेवा जारी रखने के लिए अनुपयुक्त हो जाता है, के कारण उत्पन्न हुए तत्काल वित्तीय संकट से निपटने का उद्देश्य, जिसके लिए नियुक्ति की पेशकश करके परोपकार दिखाया जाता है, शायद मौजूद न रहे और इस प्रकार ऐसी नियुक्ति का मूल उद्देश्य ही विफल हो सकता है – केवल इसलिए दावा खारिज करना विवेकपूर्ण या बुद्धिमानी नहीं है क्योंकि न्यायालयों को अपने समक्ष विचाराधीन मुद्दे पर निर्णय लेने में समय लगा है – तथापि, विलंब से किए गए दावे के मामलों में समय की चूक करुणा नियुक्ति से इनकार करने का एक प्रमुख कारक हो सकती है – विलंब से दायर किए गए दावों के मामलों में यह अनुमान वैध रूप से लगाया जाता है कि मृतक/अक्षम कर्मचारी का परिवार तत्काल वित्तीय सहायता की आवश्यकता में नहीं है – हालांकि, उचित समय क्या होगा, यह बड़े पैमाने पर विचाराधीन अनुकम्पा नियुक्ति की नीति/योजना पर निर्भर करेगा – यदि आवेदन करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है और दावेदार उस अवधि के भीतर आवेदन करता है, तो अस्वीकृति के आधार के रूप में समय की चूक को नहीं बताया जा सकता है – इस तत्काल मामले में प्रतिवादी के पिता की मृत्यु दिसंबर 2001 में हुई थी – अब, 2025 है – प्रतिवादी

को देरी के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वह अपीलकर्ता के समक्ष और उसके बाद उच्च न्यायालय के समक्ष अपने दावे का लगन से पीछा कर रहा था — इस प्रकार, प्रतिवादी वर्तमान में कितना भी वृद्ध क्यों न हो, उसकी आयु उसके दावे को समाप्त करने के लिए निर्धारक नहीं हो सकती है और न ही गुण-दोष के आधार पर उसी पर विचार करने से रोक सकती है। [कंडिका 25, 26, 27 और 28]

सेवा विधि — अनुकम्पा नियुक्ति — मृतक के परिवार की वित्तीय स्थिति के आकलन को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है:

अभिनिर्धारित: वर्तमान मामले में, केवल मृतक की पत्नी और पुत्र (प्रत्यर्थी) ही आश्रित माने जा सकते थे — यदि प्रत्यर्थी के पिता को 6398/- रुपये की पेंशन राशि प्राप्त होती और उन पर अपना तथा अपने दो आश्रितों का भरण-पोषण करने का बोझ होता, तो परिवार पेंशन की वह राशि जो शुरू में स्वीकृत की गई थी, यानी 4637.92 रुपये, दो व्यक्तियों के भरण-पोषण के लिए अपर्याप्त या नाकाफ़ी नहीं मानी जा सकती थी — यह भी विवादित नहीं है कि प्रत्यर्थी/उनकी माता को 3.09 लाख रुपये की राशि में दिए गए शुद्ध सेवांत लाभ (नेट टर्मिनल बेनेफिट्स) वही राशि होती जो मृतक को अधिवर्षिता (सुपरएनुएशन) के बाद सेवांत लाभ के रूप में प्राप्त होती, यदि वह जीवित होते — इस प्रकार, यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ प्रत्यर्थी के पिता की मृत्यु ने ऐसा कोई भयानक परिणाम और/या विनाशकारी नतीजा ला दिया हो कि प्रत्यर्थी और उनकी माता को दयनीय प्रभावों का सामना करना पड़ा हो, जिसका निवारण, जैसा कि प्रत्यर्थी ने तर्क दिया, केवल अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की पेशकश करके ही किया जा सकता था — 1993 की योजना अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावेदार की उपयुक्तता के आकलन की परिकल्पना करती है — कई निर्णयों में यह माना गया है कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए नीति/योजना के भाग के रूप में गठित खंडों का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए — वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी को उपयुक्तता परीक्षा के अधीन किए बिना, खंडपीठ ने सीधे तौर पर प्रत्यर्थी को लिपिक के पद पर नियुक्ति का निर्देश देकर त्रुटि की — प्रत्यर्थी ने आगे तर्क दिया कि उन्हें आयु में छूट दी जानी चाहिए थी — शुरू में लिया गया यह निर्णय कि प्रत्यर्थी अधिक आयु के हो गए थे, मुकदमे के पहले दौर में रद्द कर दिया गया था और इसलिए, 'पूर्वन्याय' (रेस ज्यूडिकाटा) का सिद्धांत निश्चित रूप से आकर्षित होता है — अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रत्यर्थी के निवेदन को अस्वीकार करने का अपीलकर्ता का आदेश त्रुटिरहित था — संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग किया गया — अपीलकर्ता को प्रत्यर्थी को 2.5 लाख रुपये का एकमुश्त भुगतान करने का निर्देश दिया गया। [कंडिका 32, 33, 34, 46, 49]

सेवा विधि — अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति — स्थापित सिद्धांत — विवेचन: [कंडिका 11]

अनुकंपा नियुक्ति — अस्पष्ट क्षेत्र — प्रश्न यह है कि अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पर विचार करने के लिए कौन सा नियम/नीति/योजना लागू होगी, अर्थात्, क्या वह नियम/नीति/योजना जो कर्मचारी की मृत्यु की तारीख को प्रचलित थी, या आवेदन पर विचार करने की तारीख को प्रचलित थी — भिन्न मत — विवेचन किया गया। [कंडिका 12-23]

सेवा विधि — अनुकम्पा नियुक्ति — उद्देश्य — अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर कब विचार किया जाना चाहिए और कब इसे स्वीकृत किया जाना चाहिए:

अभिनिर्धारित: सेवाकाल में मृत्यु के मामलों में अनुकंपा नियुक्ति के पीछे का मूल विचार यह प्रतीत होता है कि कर्मचारी, जो परिवार का एकमात्र कमाने वाला था, के असामयिक और अप्रत्याशित निधन से परिवार के सदस्य ऐसी विपन्न स्थिति में आ जाते हैं कि यदि उन्हें अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति न दी जाए, तो वे जीवित नहीं रह पाएँगे — सेवाकाल में मृत होने वाले कर्मचारियों के सभी मामलों पर एक समान रूप से लागू होने वाला कोई 'कठोर मानदंड' नहीं हो सकता, जो अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की वारंटी देगा — प्रत्येक मामले की अपनी विशिष्ट विशेषताएँ होती हैं और उस पर परिवार की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए निपटा जाना आवश्यक है — यह केवल 'तंगी की स्थिति वाले' मामलों में ही है कि अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर विचार किया जाना चाहिए और, यदि अन्य सभी शर्तें पूरी होती हैं, तो उसे स्वीकृत किया जाना चाहिए — ऐसे 'तंगी की स्थिति वाले' मामलों में वे मामले शामिल होंगे जहाँ मृतक का परिवार 'गरीबी रेखा से नीचे' है और जीविका के किसी स्थिर स्रोत के अभाव के कारण भोजन, किराया, उपयोगिताएँ आदि जैसे बुनियादी खर्चों का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहा है — इसे, कमाने वाले की मृत्यु के कारण जीवन स्तर में आई मात्र गिरावट से, अलग समझना होगा। [कंडिका 29]

सेवा विधि – अनुकम्पा नियुक्ति – उसके लिए दावा – दावेदार की आयु – क्या आयु में छूट प्रदान की जानी चाहिए:

अभिनिर्धारित: आयु में छूट का प्रश्न तभी उत्पन्न होगा जब दावेदार अनुकंपा नियुक्ति की योजना की अन्य अपेक्षाओं को पूरा करता हो — किसी भी आश्रित को, जो उपयुक्तता सहित अनुकंपा नियुक्ति के लिए अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता हो, केवल 'आयु-बाधा' के आधार पर ही प्रारम्भिक स्तर पर बाहर नहीं किया जाना चाहिए— यदि दावेदार की आयु छूट योग्य सीमा के भीतर पाई जाती है, तो उचित मामले में विवेक का प्रयोग करने का अधिकार उपलब्ध है — आयु में छूट संपूर्ण प्रक्रिया के अंतिम चरणों में उठाया जाने वाला कदम है और इस पर तभी विचार किया जाएगा जब नियुक्ति के लिए अन्य सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं — वर्तमान मामले में, मृतक का परिवार 'निर्धन' नहीं पाया गया है, पहला मानदंड पार नहीं किया गया है और इस प्रकार, प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती है — ऐसे मामले में, यह विचार करना कि क्या आयु में छूट दी जानी चाहिए, एक 'निष्क्रिय औपचारिकता' होगी।[कंडिका 35]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 – आदेश 41, नियम 33 – अपीलीय न्यायालय – शक्तियाँ – चर्चा की गई:

अभिनिर्धारित: अपील न्यायालय की शक्ति विधियों द्वारा परिधिबद्ध होती है — जब तक अपील में कोई प्रकरण इतना असाधारण न हो कि अपीलीय न्यायालय यह आवश्यक समझे कि वह ऐसी शक्ति का प्रयोग करे जो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 33 द्वारा अपीलीय न्यायालयों को प्रदत्त शक्ति के समान हो, तब तक सामान्यतः ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।[कंडिका 36]

उद्धृत न्यायदृष्टान्त

केनरा बैंक बनाम एम. महेश कुमार [2015] 9 एससीआर 724:(2015) 7 एससीसी 412 – संशयास्पद।

उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य [1994] 3 एससीआर 893:(1994) 4 एससीसी 138;
भारत संघ बनाम बी. किशोर [2011] 5 एससीआर 719:(2011) 13 एससीसी 131 – अनुसरण किया गया।

महाप्रबंधक (डी एंड पीबी) बनाम कुंती तिवारी (2004) 7 एससीसी 271 – अभिमुख।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम सोमवीर सिंह [2007] 2 एससीआर 509:(2007) 4 एससीसी 778; हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड बनाम हाकिम सिंह [1997] अनुपूरक 4 एससीआर 377:(1997) 8 एससीसी 85; जनरल मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम अंजू जैन [2008] 12 एससीआर 576:(2008) 8 एससीसी 475; हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड बनाम कृष्णा देवी (2002) 10 एससीसी 246; वी. शिवमूर्ति बनाम भारत संघ [2008] 11 एससीआर 1201:(2008) 13 एससीसी 730; सुषमा गोस्वामी बनाम भारत संघ (1989) 4 एससीसी 468; उत्तरांचल जल संस्थान बनाम लक्ष्मी देवी (2009) 7 एससीसी 205; सेल बनाम मधुसूदन दास [2008] 14 एससीआर 824:(2008) 15 एससीसी 560; छत्तीसगढ़ राज्य बनाम धीरजो कुमार सेंगर [2009] 7 एससीआर 1016:(2009) 13 एससीसी 600; भवानी प्रसाद सोनकर बनाम भारत संघ [2011] 4 एससीआर 630:(2011) 4 एससीसी 209; भारत संघ बनाम अमृता सिन्हा [2021] 9 एससीआर 602:(2021) 20 एससीसी 695; ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम अनिल बड्याकर [2009] 9 एससीआर 480:(2009) 13 एससीसी 112; आई.जी. (कार्मिक) बनाम प्रहलाद मणि त्रिपाठी [2007] 5 एससीआर 978:(2007) 6 एससीसी 162; गुजरात राज्य बनाम अरविंदकुमार टी. तिवारी [2012] 7 एससीआर 1072:(2012) 9 एससीसी 545; संजय कुमार बनाम बिहार राज्य [2000] अनुपूरक 2 एससीआर 710:(2000) 7 एससीसी 192; नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाम नीरज कुमार सिंह [2007] 2 एससीआर 184:(2007) 2 एससीसी 481; हरियाणा लोक सेवा आयोग बनाम हरिंदर सिंह (1998) 5 एससीआर 452; भारत संघ बनाम शशांक गोस्वामी [2012] 6 एससीआर 98 : (2012) 11 एससीसी 307; यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम एम. टी. लथीश [2006] अनुपूरक 4 एससीआर 696:(2006) 7 एससीसी 350; नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन बनाम नानक चंद [2004] Supp. 5 एससीआर 596:(2004) 12 एससीसी 487; पंजाब नेशनल बैंक बनाम अश्विनी कुमार तनेजा [2004] अनुपूरक 3 एससीआर 597:(2004) 7 एससीसी 265; बलबीर कौर बनाम सेल [2000] 3 एससीआर 1053:(2000) 6 एससीसी 493; हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम शशि कुमार [2019] 2 एससीआर 432:(2019) 3 एससीसी 653; भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम आशा रामचंद्र अंबेकर [1994] 2 एससीआर 163:(1994) 2 एससीसी 718; एसबीआई बनाम जसपाल कौर [2007] 2 एससीआर 101:(2007) 9 एससीसी 571; केंद्रीय विद्यालय संगठन बनाम धर्मेन्द्र शर्मा [2007] 9 एससीआर 1007:(2007) 8 एससीसी 148; अभिषेक कुमार बनाम हरियाणा राज्य [2006] अनुपूरक 10 एससीआर 37:(2006) 12 एससीसी 44; एसबीआई बनाम राज कुमार (2010) 11 एससीसी 661; एम.जी.बी. ग्रामीण बैंक बनाम चक्रवर्ती सिंह [2013] 10 एससीआर 1:(2014) 13 एससीसी 583; स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम शिव शंकर तिवारी [2019] 3 एससीआर 718:(2019) 5 एससीसी 600; एन.सी. संतोष बनाम कर्नाटक राज्य [2020] 3 एससीआर 1177:(2020) 7

एससीसी 617; मध्य प्रदेश राज्य बनाम अमित श्रीवास [2020] 11 एससीआर 46: (2020) 10 एससीसी 496; गुजरात राज्य बनाम अरविंद टी. तिवारी [2012] 7 एससीआर 1072:(2012) 9 एससीसी 545; इंडियन बैंक बनाम प्रोमिला [2020] 1 एससीआर 408:(2020) 2 एससीसी 729; मध्य प्रदेश राज्य बनाम आशीष अवस्थी [2021] 7 एससीआर 444:(2022) 2 एससीसी 157; बेग राज सिंह बनाम यू.पी. राज्य [2002] अनुपूरक 5 एससीआर 530:(2003) 1 एससीसी 726; निदेशक बंदोबस्त, ए.पी. बनाम एम.आर. अप्पाराव [2002] 2 एससीआर 661: (2002) 4 एससीसी 638 – संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; भारत का संविधान।

कीवर्ड की सूची

अनुकंपा नियुक्ति; समय का व्यतीत होना; दावा प्रस्तुत करने वाले की आयु; आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन; आयु में छूट; अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ।

किससे उद्भूत मामला

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील क्रमांक 255/2025

डब्लू संख्या 1364/2016 में केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम के निर्णय और आदेश दिनांक 04.11.2019 से

पक्षकारों की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता:

राजेश कुमार गौतम, अनंत गौतम, दीपांजल चौधरी, दिनेश शर्मा, कुशाग्र निलेश सहाय।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता:

निशे राजेन शोंकर, श्रीमती अनु के. जॉय, अलीम अनवर, सन्तोष के., मोहम्मद सादिक टी.ए.

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति श्री दीपांकर दत्ता

अपील

1. कैनेरा बैंक¹ विशेष अनुमति द्वारा इस अपील में है, जो दिनांक 4 नवम्बर 2019² को केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम³ की खंडपीठ द्वारा पारित उस निर्णय एवं आदेश से व्यथित है, जिसने अंतर-न्यायालय अपील को खारिज कर दिया था। यह अपील बैंक ने एकल पीठ के 9 जून, 2016 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध दायर की थी, जिसने अजितकुमार जी.के.⁴ की रिट याचिका को स्वीकार कर लिया था।

तथ्यों का सारांश

2. इस अपील का कारण बनने वाले तथ्य विवादित नहीं हैं। हालाँकि, अपील का निर्णय लेने के लिए तथ्यों का एक संक्षिप्त सारांश आवश्यक माना जाता है।

क. उत्तरवादी के पिता का निधन 20 दिसंबर, 2001 को अपीलकर्ता की सेवा में रहते हुए हो गया था। सेवानिवृत्ति से पहले उनकी 4 (चार) महीने की सेवा शेष थी।

ख. जब यह निधन हुआ, तब अपीलकर्ता द्वारा बनाई गई और 8 मई 1993⁵ को जारी परिपत्र संख्या 154/93 में निहित, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की एक योजना लागू थी। अपने पिता की मृत्यु के एक महीने के भीतर, प्रतिवादी ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए 15 जनवरी, 2002 को आवेदन किया।

ग. 30 अक्टूबर, 2002 को, अपीलकर्ता के उप महाप्रबंधक द्वारा प्रतिवादी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। दिए गए कारण दोहरे थे: (i) प्रतिवादी की माँ 4367.92 रुपये का पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रही हैं और इसलिए परिवार की वित्तीय स्थिति अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की आवश्यकता नहीं दर्शाती है; और (ii) प्रतिवादी 'प्रोबेशनरी चपरासी' के पद के लिए अधिक आयु का था।"

ड. संयोगवश, प्रतिवादी की आयु 26 (छब्बीस) वर्ष से अधिक थी और 1993 की योजना के अनुसार, लिपिकीय पद के साथ-साथ उप-कर्मचारी श्रेणी में नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 26 (छब्बीस) वर्ष थी। हालाँकि, उक्त योजना में ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम पाँच वर्ष तक की छूट का प्रावधान था। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए, विशेष छूट का भी प्रावधान था। प्रतिवादी, यद्यपि कुछ महीनों से अधिक आयु का था, फिर भी अपीलकर्ता द्वारा ऐसी छूट के लिए उस पर विचार नहीं किया गया।

च. इसके बावजूद, प्रतिवादी ने 7 जनवरी, 2003 को अपने अनुरोध पर पुनर्विचार करने की प्रार्थना की।

छ. अपीलकर्ता के सहायक महाप्रबंधक ने 20 जनवरी, 2003 को प्रतिवादी को यह सूचित किया कि मृतक कर्मचारी के परिवार की वित्तीय स्थिति की जाँच सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले ही गहनता से की जा चुकी है, और पुनर्विचार के लिए कोई नया आधार नहीं होने के कारण, उन्होंने अनुरोध पर पुनर्विचार करने में असमर्थता व्यक्त की।

ज. इसके बाद, 4 फरवरी, 2003 को प्रतिवादी की माँ ने एक अनुरोध किया, जिसमें उन्होंने अपीलकर्ता की 24 (चौबीस) वर्ष से अधिक समय तक सेवा करने वाले मृतक कर्मचारी के गरीब परिवार की सुरक्षा के लिए प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर पुनर्विचार करने की माँग की।

झ. 18 फरवरी, 2003 के एक आदेश द्वारा, अपीलकर्ता के मंडल प्रबंधक ने एक बार फिर प्रतिवादी की माँ के आवेदन पर पुनर्विचार करने में असमर्थता व्यक्त की।

ञ. अन्य कोई विकल्प न पाकर, प्रतिवादी ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका⁶ प्रस्तुत करके केरल उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान किया।

ठ. उपरोक्त रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्ता ने 14 फरवरी, 2005⁷ को परिपत्र संख्या 35/2005 जारी किया, जिसमें 'अनुकंपा के आधार पर रोजगार के बदले में एकमुश्त अनुग्रह राशि के भुगतान की योजना' शुरू की गई। उक्त योजना में मृतक कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान था, जो एकमुश्त अनुग्रह राशि के भुगतान के हकदार होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि 14 फरवरी, 2005 के इस परिपत्र द्वारा 1993 की योजना के अंतर्गत सहानुभूति नियुक्ति की नीति को बंद कर दिया गया।

ड. जैसा कि देश भर के उच्च न्यायालयों में काम का अत्यधिक बोझ होता है, जबकि न्यायाधीशों की संख्या स्वीकृत संख्या से कम होती है, और अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों से, उच्च न्यायालय को रिट याचिका का निर्णय लेने में एक दशक से अधिक का समय लग गया।

इ. 16 जून, 2015 के निर्णय एवं आदेश के द्वारा रिट याचिका स्वीकार कर ली गई। उप महाप्रबंधक द्वारा 30 अक्टूबर, 2002 को पारित वह आदेश, जिसमें प्रतिवादी को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से इनकार किया गया था, उसे उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा शुरू की गई 1993 की योजना के बिल्कुल भी अनुरूप नहीं माना; इसके अतिरिक्त, यह माना गया कि प्रतिवादी और उसकी माँ के अनुरोध पर पुनर्विचार करते समय, अपीलकर्ता ने योजना के प्रशंसनीय उद्देश्य पर, विशेष रूप से उसके कंडिका 5.1 के तहत प्रदान की गई आयु में छूट देने की शक्ति पर, उचित रूप से ध्यान नहीं दिया; यह भी कि चुनौती दिए गए आदेशों को रद्द किए जाने योग्य माना गया। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता को निर्देश दिया गया कि वह 1993 की योजना के साथ-साथ इस न्यायालय के निर्णयों - **केनरा बैंक बनाम एम महेश कुमार⁸** और **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम सोमवीर सिंह⁹** - में निर्धारित सिद्धांतों, और प्रतिवादी द्वारा बताए गए किसी भी अन्य प्रासंगिक निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर पुनर्विचार करे। तदनुसार, चुनौती दिए गए आदेशों को खारिज करने पर, अपीलकर्ता को निर्देश दिया गया कि वह निर्देशानुसार 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस मामले में निर्णय ले।

ढ. उपरोक्त निर्णय और आदेश के अनुपालन में, अपीलकर्ता के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी¹⁰ ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रतिवादी के दावे की पुनः जाँच की और एक बार फिर दावे पर सकारात्मक विचार करने से इनकार कर दिया। 8 सितंबर, 2015 को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पारित आदेश के प्रासंगिक अंश इस प्रकार हैं:

"श्री अजित कुमार जी के के इस विशेष मामले में, निम्नलिखित तथ्य अविवादित हैं:

- पूर्व-कर्मचारी की मृत्यु केवल 4 महीने से थोड़ी अधिक की शेष सेवा के साथ हुई और आश्रित परिवार पूर्ण टर्मिनल लाभों (बकाया देनदारियों की वसूली के बाद सकल ₹3.23 लाख और शुद्ध ₹3.09 लाख) और 2002 के दौरान ₹4637.92 की पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र था।
- उन्होंने अपने पीछे अपनी पत्नी और एक अविवाहित पुत्र को छोड़ा था।
- तीनों बेटियाँ विवाहित थीं और वे बस चुकी थीं।
- आवेदन की तिथि पर पुत्र की आयु 26 वर्ष और 8 महीने थी।
- मृतक का परिवार केनरा बैंक पेंशन विनियमों के तहत पेंशन प्राप्त कर रहा था।

इसलिए, जांच करने का प्राथमिक और सबसे मूलभूत मुद्दा यह है कि क्या मृतक कर्मचारी के आश्रित को कर्मचारी की अचानक मृत्यु के कारण किसी तत्काल वित्तीय कठिनाई या घोर निर्धनता का सामना करना पड़ रहा था।

इस वर्तमान मामले में, परिवार में कोई अवयस्क आश्रित बच्चे या अविवाहित पुत्री नहीं थी जिनके लिए भविष्य में वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती। मृतक कर्मचारी की तीनों पुत्रियाँ उनकी मृत्यु के समय पहले से ही विवाहित और स्थापित थीं। अन्य प्रत्यक्षदर्शी उनकी पत्नी और पुत्र श्री अजित कुमार हैं, जिनकी आयु उस समय 26 वर्ष और 8 महीने थी। यह परिवार अपने ही घर में रह रहा था। श्री वी.सी. गोपालकृष्ण पिल्लई का 2001 में अंतिम शुद्ध वेतन ₹9,772/- था, और यदि वह और 4 महीने जीवित रहते, तो वह बैंक से प्राप्त होने वाली पेंशन (सामान्य तौर पर लगभग ₹6,398/- मात्र) से अपने परिवार का भरण-पोषण करते। कर्मचारी के निधन के बाद, उनकी पत्नी श्रीमती ओमना अम्मा के लिए ₹4,637.92 की पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की गई थी, जो वर्तमान में ₹5,825/- प्रति माह है। इसके अलावा, 2002 में आश्रितों के लिए ₹3.09 लाख के शुद्ध टर्मिनल लाभ (₹13,942/- की देनदारी बंद करने के बाद) भी उपलब्ध थे।

सभी कारकों और उस समय की पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरा यह सुविचारित मत है कि स्वर्गीय श्री वी. सी. गोपालकृष्ण पिल्लई के आश्रित परिवार की ऐसी कोई भी निर्धनता वाली स्थिति कभी मौजूद नहीं थी, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि परिवार इतने बड़े संकट में था जिससे वह अनुकंपा नियुक्ति की पेशकश के बिना उबरने में सक्षम नहीं होता।

उपर्युक्त कारणों से, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि आश्रित परिवार उस समय किसी तीव्र वित्तीय संकट या घोर निर्धनता का सामना नहीं कर रहा था, जो इस मामले में अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देने के लिए विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग को उचित ठहराता हो।

आयु में छूट का प्रश्न तभी उठता है जब आवेदक अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र हो। चूंकि मैंने यह पाया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर, जिसके अनुसार यह योजना बनाई गई है, आवेदक अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। इसलिए, मैं योजना के अनुसार आयु में छूट के प्रश्न पर विचार नहीं कर रहा हूँ।

अतः, पूरे मामले पर विचार करते हुए और उस समय विद्यमान वित्तीय एवं पारिवारिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, स्वर्गीय वी. सी. गोपालकृष्ण पिल्लई (22841), जो त्रिकोविलवट्टम शाखा के पूर्व-क्लर्क थे, के आश्रितों के लिए अनुकंपा नियुक्ति के अनुरोध को सकारात्मक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है।

इसलिए, श्री अजित कुमार जी.के. द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए दिया गया आवेदन और अभ्यावेदन अस्वीकृत किया जाता है।"

ण. नियुक्ति से पुनः इनकार किए जाने पर प्रतिवादी निराश हो गया। इस प्रकार, उसने एक रिट याचिका¹¹ प्रस्तुत करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिससे

मुकदमेबाजी का दूसरा दौर शुरू हुआ जो अब इस न्यायालय तक पहुँच चुका है। 9 जून, 2016 के निर्णय और आदेश में बताए गए कारणों से, उच्च न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया। प्रबंध निदेशक द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को अपास्त कर दिया गया। यह निर्देश दिया गया कि प्रतिवादी को 1993 की योजना के तहत उप-कर्मचारी संवर्ग में 2 (दो) महीने के भीतर नियुक्ति के लिए विचार किया जाए। इसके अलावा, यह भी निर्देश दिया गया कि समय पर अनुकंपा नियुक्ति देने में दिखाई गई अनिच्छा के लिए अपीलकर्ता प्रतिवादी को मुआवजे के रूप में ₹5 (पाँच) लाख की राशि का भुगतान भी करेगा।

त. अपीलकर्ता, पूर्णतः असंतुष्ट होकर, एक अंतः-अदालती अपील¹² दायर की। उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने अपने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा इस अपील को खारिज कर दिया, साथ ही एकल न्यायाधीश द्वारा चुनौती दिए गए निर्णय और आदेश में दिए गए मुआवजे के अलावा, ₹5 (पाँच) लाख का उदाहरण योग्य जुर्माना भी लगाया। खंडपीठ ने उस तरीके पर आश्चर्य व्यक्त किया जिस तरह से अपीलकर्ता और उसके अधिकारियों ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रतिवादी के दावे को संभाला था। खंडपीठ ने अपीलकर्ता की किसी भी शाखा में एक महीने के भीतर प्रतिवादी को उप-कर्मचारी श्रेणी में नियुक्त करने का निर्देश दिया।

थ. खंडपीठ के उपरोक्त निर्देशों के कारण कंडिका 17 और 18 में निहित हैं, जो इस प्रकार हैं:

“17. हम नहीं सोचते कि अपीलकर्ता-बैंक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए किसी भी निर्णय के कारण हमें विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय में हस्तक्षेप करना चाहिए। जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने ध्यान दिया, एम. महेश कुमार और प्रिया जयराजन के निर्णयों ने उसी बैंक की समान योजना के तहत इस मुद्दे को निपटाया है, जो वहाँ भी अपीलकर्ता था। एम. महेश कुमार में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि पारिवारिक पेंशन प्रदान करना और सेवांत लाभों का भुगतान करना अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का विकल्प नहीं माना जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 15.05.2015 को निर्णय दिए जाने के बावजूद, विद्वान एकल न्यायाधीश ने जैसा सही पाया, उसी अपीलकर्ता के मामले में 2015 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा धारण किए जाने के बावजूद, दिनांक 08.09.2015 के प्रदर्श पीठ द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत आदेश पारित करना बैंक की ओर से एक दुस्साहसिक कार्य था।

18. बैंक ने न केवल अपने ही मामले में दिए गए निर्णय के विपरीत आदेश पारित किया, बल्कि रिट याचिका खारिज करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील भी दायर की। हम ध्यान देते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने मृतक के शोकाकुल परिवार को, वह भी योजना के प्रावधानों के विपरीत जाकर, दयनीय स्थिति में भटकने देने के लिए ₹5 लाख रुपये का अनुकरणीय हर्जाना मंजूर किया था। हम इस तथ्य पर भी ध्यान देते हैं कि बैंक ने पिछली रिट याचिका में आयु में छूट पर विचार करने के निर्देश को भी दरकिनार कर दिया था। परिस्थितियों की समग्रता में, विशेष रूप से तब जब पुत्र अधिकतम आयु सीमा से केवल आठ महीने अधिक था, यही प्रासंगिक और एकमात्र विचार था जो किया जाना चाहिए था। पारिवारिक पेंशन की प्राप्ति, जिसे एक प्रासंगिक

विचार नहीं पाया गया था, को भी नियुक्ति अस्वीकार करने का कारण बताया गया। हम दोहराते हैं कि संपूर्ण योजना को पढ़ने पर, विशेष रूप से विशेष प्रावधानों को जो एक आश्रित को नियुक्त करने में सक्षम बनाते हैं, भले ही दूसरा कार्यरत हो, हमें यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करते हैं कि वर्तमान दावे को केवल पारिवारिक पेंशन और ₹3.09 लाख रुपये के सेवानिवृत्ति लाभ के कारण अस्वीकार करना योजना की भावना और आशय के विपरीत है।"

द. इस प्रकार, केनरा बैंक उक्त निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील में है।

पक्षकारों के तर्क

3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार:

क. एकल न्यायाधीश और खंडपीठ द्वारा **केनरा बैंक** (उपरोक्त) के निर्णय की कंडिका 19 पर दिया गया भरोसा गलत था। प्रथमतः, इसलिए कि विचाराधीन मामला उस विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से काफी भिन्न है और द्वितीयतः, इसलिए कि पैरा 19 की सामग्री केवल टिप्पणियाँ मात्र थीं और वे बाध्यकारी पूर्व दृष्टांत का गठन नहीं करती हैं। उक्त निर्णय में यह प्रश्न न तो उठाया गया था और न ही इसका समाधान किया गया था कि क्या मृतक कर्मचारी के परिवार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने में सेवांत लाभों को शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, **केनरा बैंक** (उपरोक्त) के निर्णय को आगे के विचारार्थ बड़ी पीठ को संदर्भित किया गया है।

ख. इसके अतिरिक्त, एकल न्यायाधीश और खंडपीठ के निर्णय इस न्यायालय द्वारा निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला में स्थापित कानूनी सिद्धांतों के साथ असंगत हैं।

ग. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित मामलों में, परिवार की समग्र वित्तीय स्थिति का आकलन करते समय मृतक कर्मचारी के परिवार को प्रदान किए जा रहे सेवांत लाभों के साथ-साथ पारिवारिक पेंशन को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

घ. आयु में छूट का प्रश्न तभी उत्पन्न होता है जब आवेदक अन्यथा अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र हो, बशर्ते कि वह दो श्रेणियों के पदों में से किसी के लिए उपयुक्त पाया जाता हो। वर्तमान मामले में, यह पाया गया था कि निर्धन परिस्थितियों के अभाव के कारण प्रत्यर्थी मांगी गई नियुक्ति के लिए पात्र नहीं था और इसलिए, आयु में छूट या उसकी उपयुक्तता का परीक्षण करने का प्रश्न, जो प्रक्रिया के अगले कदम हैं, उठाए जाने की आवश्यकता नहीं थी। अतः उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी के दावे को स्वीकार करने के लिए गलत मानदंडों को लागू किया।

4. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि:

क. 1993 की योजना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि अनुकंपा के आधार पर रोजगार देने से पहले आवेदक के परिवार की वित्तीय स्थिति पर विचार किया जाए। **केनरा बैंक** (उपरोक्त) के इस न्यायालय के निर्णय के पैरा 19 का संदर्भ इस तर्क के समर्थन में दिया गया कि पिता की मृत्यु के बाद अपीलकर्ता के लिए प्रत्यर्थी की वित्तीय स्थिति का 'जुमला' उठाना सही नहीं था, क्योंकि यह निर्धन परिस्थितियों को नहीं दर्शाता था। अतः, प्रत्यर्थी के दावे को केवल इस आधार पर अस्वीकार करना कि परिवार को पेंशन और अन्य सेवांत लाभ प्राप्त हो रहे हैं, **केनरा बैंक** (उपरोक्त) के निर्णय का उल्लंघन है, जो अपीलकर्ता पर बाध्यकारी है।

ख. आयु-सीमा के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रत्यर्थी के अपात्र होने का अपीलकर्ता का तर्क असमर्थनीय नहीं है। अपीलकर्ता ने 15 जनवरी, 2002 के प्रत्यर्थी के प्रारंभिक आवेदन को अस्वीकार करने वाले 30 अक्टूबर, 2002 के पत्र को छोड़कर, अन्य पत्रों और प्रत्युत्तर शपथ पत्रों में प्रत्यर्थी के अधिक आयु होने पर कोई आपत्ति नहीं उठाई थी। इसके अलावा, पूर्व न्याय के सिद्धांत के मद्देनजर 16 जून, 2015 के उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा 30 अक्टूबर, 2002 के पत्र में निहित निर्णय को रद्द किए जाने के कारण, अधिक आयु का मुद्दा बाद में नहीं उठाया जा सकता था।

ग. इसके अलावा, अपीलकर्ता के पास आयु में छूट देने की शक्ति थी और वर्तमान मामले में ऐसी छूट की शक्ति पर विचार किए बिना, अपीलकर्ता ने सेवांत लाभों और पारिवारिक पेंशन की प्राप्ति के कारण आवेदन को अवैध रूप से और मनमाने तरीके से अस्वीकार कर दिया।

घ. इसके अलावा, अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि अपीलकर्ता ने मृतक के परिवार की वित्तीय स्थिति का कोई सद्भाविक मूल्यांकन किया था। अपीलकर्ता के निवेदनों से यह अनुमान किया जा सकता है कि वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि परिवार की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है, केवल इस आधार पर कि परिवार को पारिवारिक पेंशन और अन्य सेवांत लाभ प्राप्त हुए, जबकि **केनरा बैंक** (उपरोक्त) के निर्णय के अनुपात को समझा नहीं गया, जहाँ सेवांत लाभों की प्राप्ति को बिल्कुल भी महत्वहीन माना गया था। अंत में, यह निवेदन किया गया कि प्रत्यर्थी के पिता की मृत्यु के बाद काफी समय बीत चुका है और प्रत्यर्थी को अनावश्यक रूप से लंबे समय तक इंतजार करवाया गया है, अतः वर्तमान अपील प्रत्यर्थी को लागत सहित खारिज किए जाने योग्य है।

5. अनुकंपा नियुक्ति के बिंदु पर दोनों पक्षकारों द्वारा हमारे समक्ष न्यायिक पूर्व दृष्टांत उद्धृत किए गए हैं। उन पर, तथा अन्य पूर्व दृष्टांतों पर, सम्यक विचार किया जाना आवश्यक है और जैसे-जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी, हमारा ऐसा करने का अभिप्राय है।

विवाद्यक

6. इस अपील पर निर्णय के लिए उत्पन्न होने वाला मूल मुद्दा यह है कि क्या उच्च न्यायालय की खंडपीठ अपीलकर्ता की अंतर-न्यायालयीन अपील को अनुमति न देकर और एकल न्यायाधीश के निर्णय को बरकरार रखते हुए, प्रत्यर्थी की नियुक्ति का निर्देश देने में अन्यायपूर्ण थी, जबकि उस समय उसकी आयु 44 (चवालीस) वर्ष से अधिक हो चुकी थी।
7. कुछ उप-मुद्दे भी हैं जिन पर हमारा ध्यान जाना आवश्यक होगा। हम 1993 की योजना की मुख्य विशेषताओं और अनुकंपा नियुक्ति के क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले अनेक न्यायिक पूर्व दृष्टांतों को नोट करने के बाद, एक बाद के चरण में, उनकी भी समीक्षा करने का प्रस्ताव करते हैं।

योजना

8. 1993 की योजना को अपीलकर्ता द्वारा पिछले सभी परिपत्रों, अनुदेशों और दिशानिर्देशों का अधित्यजन करते हुए प्रस्तुत किया गया था। इस योजना का उद्देश्य इस प्रकार वर्णित है:

"उद्देश्य: अनुकम्पा आधार पर रोजगार प्रदान करने की यह योजना (जिसे आगे 'योजना' कहा जाएगा), उन कर्मचारियों के आश्रितों की सहायता के लिए विकसित की गई है, जो सेवाकाल के दौरान मृत हो जाते हैं अथवा पूर्ण रूप से और स्थायी तौर पर निःशक्त हो जाते हैं। इसका उद्देश्य आय के मुख्य स्रोत के अचानक बंद हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली तात्कालिक वित्तीय कठिनाइयों को दूर करना है।

'योजना' के अंतर्गत नियुक्ति पर विचार केवल तभी किया जाएगा, जब आश्रितों में से किसी एक को नियोजन की आवश्यकता दर्शाने वाली दरिद्र परिस्थितियाँ विद्यमान हों और दिवंगत कर्मचारी का सेवा अभिलेख बेदाग हो। मात्र पात्रता से ही नियोजन का दावा करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। बैंक इस 'योजना' के अंतर्गत प्राप्त किसी भी आवेदन को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

1993 की योजना की अन्य उल्लेखनीय विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

“3.नियोजन की मांग हेतु निर्धारित अवधि

3.1 नियोजन हेतु आवेदन कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से 2½ (ढाई) वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

3.2 यदि मृतक कर्मचारी के जिस आश्रित को नियुक्ति प्रदान की जानी है वह अवयस्क हो, तो मृतक कर्मचारी के परिवार द्वारा बैंक को अनुरोध किए जाने पर बैंक नियुक्ति के प्रस्ताव को तब तक खुला रख सकता है जब तक कि वह अवयस्क वयस्कता की आयु प्राप्त न कर ले। यह सुविधा इस शर्त पर प्रदान की जाएगी कि दिवंगत कर्मचारी के परिवार द्वारा बैंक से इस आशय का अनुरोध किया जाता है और इस अनुरोध पर, विचार के समय प्रचलित नियमों के अधीन, विचार किया जा सकता है।

5. आयु मानदंड:

क. विधवा/विधुर के मामले में

न्यूनतम – 18 वर्ष

अधिकतम – कोई विशिष्ट उच्च आयु-सीमा निर्धारित नहीं है, परंतु आयु सेवानिवृत्ति आयु से कम होनी चाहिए।

ख. अन्यो के मामले में

न्यूनतम – 18 वर्ष

अधिकतम – लिपिकीय पद एवं उप-कर्मचारी श्रेणी दोनों के लिए आयु 26 वर्ष।

ऊपरी आयु-सीमा, एससी/एसटी/भूतपूर्व सैनिक/विकलांग अभ्यर्थियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में प्रचलित मानकों के अनुसार निम्नलिखित रूप से छूट दी जाएगी:

एससी/एसटी – 5 वर्ष

भूतपूर्व सैनिक – 3 वर्ष की सेवा + सशस्त्र बलों में की गई सेवा।

विकलांग – 10 वर्ष

5.1 जहां मृतक कर्मचारी का कोई भी आश्रित, जो निर्धारित आयु सीमा के भीतर हो, नियोजन हेतु उपलब्ध नहीं है, वहां बैंक स्वविवेक से अधिकतम 5 वर्ष की सीमा तक ऊपरी आयु सीमा में छूट दे सकता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित आश्रितों के मामले में, ऊपरी आयु सीमा के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु

मौजूदा रियायत लागू रहेगी, किंतु किसी भी स्थिति में यह दस वर्ष से अधिक नहीं होगी, अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार होने के लिए 5 वर्ष और स्वविवेक शक्तियों के तहत अन्य 5 वर्ष, बशर्ते कि निर्धारित आयु सीमा के भीतर कोई अन्य आश्रित उपलब्ध न हो।

9. आवेदन करने की प्रक्रिया कंडिका 11 में दी गई है, जिसके लिए आवश्यक है कि आवेदन परिशिष्ट 'I' से 'III' में दिए गए प्रारूपों में किए जाएं, जबकि कंडिका '12' में यह अधिनियमित किया गया था कि नियोजन का प्रस्ताव केवल एक ही व्यक्ति तक सीमित रहेगा।

अनुकंपा नियुक्ति के मुद्दे पर न्याय दृष्टांत

10. किसी कर्मचारी के, जो सेवाकाल में मृत्यु को प्राप्त हो गया हो अथवा चिकित्सकीय रूप से आगे कार्य करने हेतु अयोग्य घोषित हो गया हो, जिससे उसका परिवार घोर विपन्नता में आ गया हो, उसके आश्रित परिवार के सदस्य को नियुक्त करने की नीति बहुत पुरानी उत्पत्ति की नहीं है। विधि रिपोर्टों के अनुसार, यह नीति पिछली शताब्दी के सत्तर के दशक में उत्पन्न हुई प्रतीत होती है और बाद के दशकों में इस न्यायालय द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने हेतु समय-समय पर दिशा-निर्देश निर्धारित किए जाने के साथ इसने गति पकड़ी। इस प्रकार की नियुक्ति का औचित्य *हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड बनाम हकीम सिंह*⁴³ में निम्नलिखित शब्दों में समझाया गया है:

“8. लोक सेवा में नियुक्तियों का नियम यह है कि वे योग्यता के आधार पर और खुले आमंत्रण के माध्यम से होनी चाहिए। यह वह सामान्य माग है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति लोक नियोजन प्राप्त कर सकता है। तथापि, चूंकि प्रत्येक नियम के अपवाद हो सकते हैं, उक्त नियम के भी कुछ अपवाद हैं जिन्हें कुछ आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। ऐसे ही एक अपवाद के अनुसार, दिवंगत कर्मचारी के शोकाकुल परिवार को उसके एक आश्रित को रिक्ति में समायोजित करके राहत प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य उस परिवार को सहायता देना है जो अपने एकमात्र भरण-पोषणकर्ता की असामयिक मृत्यु के कारण अचानक गरीबी में डूब गया है। इस न्यायालय ने समय-समय पर यह अवलोकन किया है कि ऐसी उपचारात्मक राहत प्रदान करने के उद्देश्य को लोक नियोजन में भर्ती का एक वैकल्पिक तरीका खोलने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।”

11. अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति की परिधि पर इस न्यायालय के निर्णय असंख्य हैं, और हमारे लिए उन कुछ सुस्थापित सिद्धांतों पर विचार करना उचित होगा, जो पूर्व दृष्टांतों के माध्यम से कानून के नियम में परिवर्तित हो गए हैं। वे निम्नलिखित हैं (क्रमिक नहीं, बल्कि प्रासंगिक/संदर्भगत क्रम में):

क). अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति, जो मानवीय आधारों पर प्रस्तावित की जाती है, लोक नियोजन के मामलों में समानता के नियम का एक अपवाद है [देखें: *जनरल मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम अंजू जैन*⁴⁴]।

ख). अनुकम्पा नियुक्ति नियमों या निर्देशों के अभाव में नहीं की जा सकती है [देखें: *हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड बनाम कृष्णा देवी*⁵]

ग). अनुकम्पा नियुक्ति सामान्यतः दो आकस्मिकताओं में प्रस्तावित की जाती है, जिन्हें सामान्य नियम के अपवाद के रूप में तराशा गया है, अर्थात्: सेवाकाल के दौरान भरण-पोषणकर्ता की या तो मृत्यु या चिकित्सीय रूप से अमान्यता के कारण परिवार में उत्पन्न हुए अचानक संकट का सामना करने के लिए [देखें: *वी. शिवमूर्ति बनाम भारत संघ*⁶]

घ). किसी नियोक्ता द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने का संपूर्ण उद्देश्य दिवंगत या निःशक्त कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को अचानक उत्पन्न हुए वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाना है। अतः, संकटग्रस्त परिवार को उबारने के लिए अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियाँ तत्काल की जानी चाहिए [देखें: *सुषमा गोसाई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया*⁷]

ङ). चूंकि अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित नियम पार्श्व-प्रवेश की अनुमति देते हैं, इसलिए उनकी कठोर व्याख्या की जानी चाहिए [देखें: *उत्तरांचल जल संस्थान बनाम लक्ष्मी देवी*⁸]

च). अनुकम्पा नियुक्ति एक रियायत है, न कि एक अधिकार, और नियमों में निर्धारित मानदंडों को सभी आवेदकों द्वारा संतुष्ट किया जाना चाहिए [देखें: *सेल बनाम मधुसूदन दास*⁹]

छ). अनुकम्पा नियुक्ति को उत्तराधिकार के रूप में कोई भी दावा नहीं कर सकता है [देखें: *स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ बनाम धीरजो कुमार सेंगर*¹⁰]

ज). केवल वंश पर आधारित नियुक्ति हमारी संवैधानिक योजना के प्रतिकूल है, और चूंकि यह एक अपवाद है, इसलिए इस योजना की कठोर व्याख्या की जानी चाहिए और इसे केवल उसी उद्देश्य तक सीमित रखा जाना चाहिए जिसे वह प्राप्त करना चाहती है [देखें: *भवानी प्रसाद सोनकर बनाम भारत संघ*¹¹]

झ). संबंधित कर्मचारी (परिवार के एकमात्र भरण-पोषणकर्ता) की मृत्यु/चिकित्सीय अक्षमता होने पर कोई भी व्यक्ति अनुकम्पा नियुक्ति पर इस प्रकार दावा नहीं कर सकता, जैसे कि यह कोई निहित अधिकार हो, और मृतक के परिवार की वित्तीय स्थिति पर विचार किए बिना कोई भी नियुक्ति वैधानिक रूप से अस्वीकार्य है [देखें: *यूनियन ऑफ इंडिया बनाम अमृता सिन्हा*¹²]

ञ). अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन कर्मचारी की मृत्यु/अक्षमता होने पर तत्काल, और किसी भी स्थिति में उसके युक्तियुक्त अवधि के भीतर किया जाना चाहिए, अन्यथा यह उपधारणा की जा सकती है कि दिवंगत/अक्षम कर्मचारी के परिवार को वित्तीय सहायता की तत्काल आवश्यकता नहीं है। चूंकि ऐसी नियुक्ति एक निहित अधिकार नहीं है, इसलिए आवेदन करने के अधिकार का प्रयोग भविष्य में किसी भी समय नहीं किया जा सकता है और संकट समाप्त होने के बाद तथा समय बीत जाने के बावजूद इसे प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है [देखें: *ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम अनिल बाद्यकर*¹³]

ट). अनुकम्पा नियोजन का उद्देश्य दिवंगत कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य को कोई पद देना नहीं है, और मृतक द्वारा धारित पद के समतुल्य पद तो बिल्कुल भी नहीं है। मृतक के परिवार की वित्तीय स्थिति पर विचार किए बिना अनुकम्पा नियोजन को एक सामान्य प्रक्रिया

के रूप में प्रस्तावित करना तथा कक्षा III और IV से ऊपर के पदों पर अनुकम्पा नियुक्तियां करना कानूनी रूप से अनुमत नहीं है [देखें: **उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य**²⁴]।

ठ). दिवंगत कर्मचारी के आश्रितों की दरिद्रता अनुकम्पा नियुक्ति की योजना के तहत मामले को लाने के लिए पहली पूर्व शर्त है। यदि अनुकम्पा नियुक्ति से दरिद्रता का तत्व और वित्तीय अभाव से राहत हेतु तत्काल सहायता प्रदान करने की आवश्यकता हटा दी जाती है, तो यह सेवाकाल में दिवंगत हुए कर्मचारी के आश्रितों के पक्ष में एक आरक्षण बन जाएगा, जो सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत गारंटीकृत समानता के आदर्श के संघर्ष में होगा [देखें: **यूनियन ऑफ इंडिया बनाम बी. किशोर**²⁵]।

ड). अनुकम्पा नियुक्ति का विचार अंतहीन अनुकम्पा प्रदान करना नहीं है [देखें: **आई.जी. (कार्मिक) बनाम प्रहलाद मणि त्रिपाठी**²⁶]।

इ). यह संतुष्टि पर्याप्त नहीं है कि परिवार के सदस्य वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं और अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति उन्हें ऐसे संकट से उबरने में सहायता कर सकती है; आश्रित को ऐसी नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड अवश्य पूरा करना चाहिए [देखें: **स्टेट ऑफ गुजरात बनाम अरविंदकुमार टी. तिवारी**²⁷]।

ढ). जब तक कि कोई विशिष्ट प्रावधान न हो, तब तक रिक्ति को उस समय तक आरक्षित नहीं किया जा सकता जब तक कि आवेदक कई वर्षों के बाद वयस्क न हो जाए [देखें: **संजय कुमार बनाम बिहार राज्य**²⁸]।

ण). पारिवारिक पेंशन का अनुदान अथवा सेवा समाप्ति लाभों का भुगतान, नियोजन सहायता प्रदान करने का विकल्प नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, यह केवल दुर्लभ मामलों में और वह भी तभी, जब अनुकम्पा नियुक्ति की योजना में इसका प्रावधान हो, अन्यथा नहीं, कि एक आश्रित जो मृत्यु/अक्षमता की तिथि पर नाबालिग था, उसे वयस्कता प्राप्त करने पर नियुक्ति के लिए विचारित किया जा सकता है [देखें: **केनरा बैंक** (उपरोक्त)]।

त). कर्मचारी की मृत्यु/अक्षमता के कई वर्षों बाद की गई अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति, या मृत/अक्षम कर्मचारी के आश्रित को उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर उचित विचार किए बिना की गई नियुक्ति, सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के विपरीत होगी [देखिए, **नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाम नीरज कुमार सिंह**²⁹]।

थ). आश्रितों को, यदि वे लाभप्रद रूप से नियोजित हैं, तो उन पर विचार नहीं किया जा सकता [देखिए, **हरियाणा लोक सेवा आयोग बनाम हरिंदर सिंह**³⁰]।

द). मृतक कर्मचारी के उत्तराधिकारियों द्वारा प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभों को इस बात का निर्धारण करने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या मृतक का परिवार घोर निर्धनता में छूट गया है। न्यायालय निर्धनता के मानदंड को 'बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति में नहीं' के मानदंड तक कम नहीं कर सकता है। [देखें **महाप्रबंधक (डी एंड पीबी) बनाम कुंती तिवारी**³¹]।

ध). मृत कर्मचारी के परिवार की वित्तीय स्थिति, कथित रूप से संकट या घोर निर्धनता में होने पर, उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, अन्यथा योजना का उद्देश्य विफल हो जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में, सेवाकाल में मरने वाले कर्मचारी का कोई भी और हर आश्रित रोजगार का दावा करेगा, मानो सार्वजनिक रोजगार वंशानुगत हो [देखें: **भारत संघ बनाम**

शशांक गोस्वामी²², यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम एम. टी. लथीश²³, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन बनाम नानक चंद²⁴ और पंजाब नेशनल बैंक बनाम अश्विनी कुमार तनेजा²⁵]

न). सेवाकालीन लाभ, निवेश, पारिवारिक पेंशन सहित मासिक पारिवारिक आय और परिवार की अन्य स्रोतों से आय, जैसे कि कृषि भूमि, को प्राधिकरण द्वारा इस बात का निर्णय लेने के लिए सही ढंग से ध्यान में रखा गया था कि परिवार दयनीय स्थिति में रह रहा है या नहीं। [देखिए *सोमवीर सिंह* (उपरोक्त)]।

प). मृतक कर्मचारी की विधवा को परिवार लाभ योजना के तहत प्राप्त होने वाले लाभ, जो मासिक भुगतान सुनिश्चित करते हैं, अनुकम्पा नियुक्ति के लिए उसके मार्ग में बाधा नहीं बन सकते। परिवार लाभ योजना को अनुकम्पा नियुक्ति के लाभों के बराबर नहीं माना जा सकता है। [देखें: *बलबीर कौर बनाम सेल²⁶*]

फ). आय स्लैब का निर्धारण वास्तव में एक ऐसा उपाय है जो मनमानी के तत्व को कम करता है। निःसंदेह, कोई निर्णय लेते समय प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों को ध्यान में रखना होता है, लेकिन आय स्लैब का निर्धारण निर्णय लेने की प्रक्रिया में निष्पक्षता और एकरूपता लाने के उद्देश्य की पूर्ति करता है। [देखें *स्टेट ऑफ एच.पी. बनाम शशि कुमार²⁷*]

ब). न्यायालय सहानुभूतिपूर्ण विचार से प्रेरित होकर वरदान प्रदान नहीं कर सकते [देखिए: *लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाम आशा रामचंद्र अम्बेकर²⁸*]

भ). न्यायालय वैधानिक विनियमों/निर्देशों के बाहर अनुकंपा नियुक्ति की अनुमति नहीं दे सकते। उम्मीदवार की कठिनाई उसे ऐसे विनियमों/निर्देशों के बाहर नियुक्ति का अधिकार नहीं देती है [देखें *एसबीआई बनाम जसपाल कौर²⁹*]

म). किसी नियोक्ता को उसकी नीति के विपरीत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है [देखिए *केंद्रीय विद्यालय संगठन बनाम धर्मेन्द्र शर्मा³⁰*]

यहाँ यह उल्लेख करना कुछ हद तक प्रासंगिक होगा कि ऊपर संदर्भित सभी निर्णय दो न्यायाधीशों की समन्वय पीठों द्वारा दिए गए हैं।

अस्पष्ट क्षेत्र

- हमारे निर्णय के लिए उभरने वाले मुद्दों पर आगे बढ़ने से पहले, हम संक्षेप में एक ऐसे क्षेत्र का उल्लेख कर सकते हैं जो कुछ साल पहले तक अनिश्चित था और अभी भी बना हुआ है। यह इस प्रश्न पर है कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए किसी आवेदन पर विचार करने हेतु कौन सा नियम/नीति/योजना लागू होगी, अर्थात्, मृत्यु की तारीख को प्रचलित नियम/नीति/योजना, या आवेदन पर विचार करने की तारीख को प्रचलित नियम/नीति/योजना।

इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा अलग-अलग विचार रखे गए हैं और ऐसे कुछ निर्णय नीचे दिए गए हैं:

क). *अभिषेक कुमार बनाम हरियाणा राज्य*⁴¹ के मामले में, यह माना गया था कि चूंकि अपीलकर्ता ने उस समय अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति मांगी थी जब 2003 के नियम अस्तित्व में नहीं थे, इसलिए उसके मामले पर 2001 में अस्तित्व में रहे नियमों के अनुसार विचार किया जाना आवश्यक था।

ख). *केनरा बैंक* (उपरोक्त) में भी यह माना गया था कि किसी विशेष वर्ष की योजना के तहत अनुकंपा नियुक्ति के दावे का निर्णय बाद की योजना के आधार पर नहीं किया जा सकता है जो दावे के बहुत बाद लागू हुई थी।

ग). तथापि, *एसबीआई बनाम राज कुमार*⁴² और *एम.जी.बी. ग्रामीण बैंक बनाम चक्रवर्ती सिंह*⁴³ में व्यक्त मत यह है कि पूर्व योजना के तहत मामले पर विचार करने का कोई निहित अधिकार नहीं है और शासक योजना वह होगी जो आवेदन विचाराधीन आने के समय लागू थी।

13. *राज कुमार* (उपरोक्त) और *चक्रवर्ती सिंह* (उपरोक्त) को *अभिषेक कुमार* (उपरोक्त) को देखने का अवसर नहीं मिला। हालांकि, *केनरा बैंक* (उपरोक्त) ने *राज कुमार* (उपरोक्त) और *चक्रवर्ती सिंह* (उपरोक्त) को देखा लेकिन उनके साथ असहमत राय व्यक्त की। *जसपाल कौर* (उपरोक्त) के फैसले पर समकक्ष पीठ द्वारा *केनरा बैंक* (उपरोक्त) में यह मानने के लिए भरोसा किया गया था कि:

"17. ... अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचारणीय कारण तब उत्पन्न हुआ जब परिपत्र संख्या 154 दिनांक 8-5-1993 लागू था। इस प्रकार, *जसपाल कौर* मामले में संदर्भित निर्णय के अनुसार, दावे का निर्णय 2005 योजना, जो अनुग्रह राशि के भुगतान का प्रावधान करती है, के अनुसार नहीं किया जा सकता है। दिनांक 14-2-2005 का परिपत्र एक प्रशासनिक या कार्यकारी आदेश होने के कारण भूतर्क्षी प्रभाव नहीं रख सकता है ताकि प्रतिवादी का 1993 के परिपत्र के अनुसार अर्जित अधिकार छीना जा सके ...।"

14. विभिन्न मतों को देखते हुए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, एक अन्य समन्वय पीठ ने इस मामले को *स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम शेओ शंकर तिवारी*⁴⁴ में एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया।
15. *शेओ शंकर तिवारी* (सुप्रा) में किए गए संदर्भ के तुरंत बाद, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने *एन.सी. संतोष बनाम कर्नाटक राज्य*⁴⁵ में माना कि अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर विचार करने के लिए, जिस तिथि को आवेदन पर विचार किया जाता है, उस तिथि को प्रचलित मानदंड ही विचार का आधार होना चाहिए। इस निर्णय की कंडिका 19 वह प्रासंगिक कंडिका है जहाँ यह सिद्धांत पाया जाता है।
16. *एन.सी. संतोष* (उपरोक्त) ने ऐसा प्रतीत होता है कि *केनरा बैंक* (उपरोक्त) को निहित रूप से अधिक्रमित कर दिया है, यह मानते हुए कि आवेदन पर विचार करने की तारीख को प्रचलित मानदंड विचार का आधार होना चाहिए न कि मृत्यु की तारीख को लागू मानदंड।
17. एक को लगा होगा कि यह मामला इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ का निर्णय होने के नाते, *एन.सी. संतोष* (उपरोक्त) के निर्णय के साथ अंतिम रूप ले चुका होगा। हालाँकि, यह विवाद इस न्यायालय के बाद के निर्णयों के कारण पुनः उभरता हुआ प्रतीत होता है, जो *अभिषेक*

कुमार (उपरोक्त) और केनरा बैंक (उपरोक्त) के अनुरूप हैं तथा राज कुमार (उपरोक्त), चक्रवर्ती सिंह (उपरोक्त) और एन.सी. संतोष (उपरोक्त) के विपरीत हैं।

18. एन.सी. संतोष (उपरोक्त) में आए फैसले के छह (6) महीने के भीतर, तीन न्यायाधीशों की एक अन्य पीठ का निर्णय स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम अमित श्रीवास¹⁶ में आया, जहाँ यह माना गया कि:

"16. यह कहना सामान्य है कि अनुकंपा नियुक्ति का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं हो सकता है, बल्कि यह कुछ मानदंडों पर आधारित एक अधिकार है, विशेष रूप से एक जरूरतमंद परिवार को सहायता प्रदान करने के लिए। यह उस तारीख को लागू नीति के अनुसार होना चाहिए जिस तारीख को निधन हुआ था, जब तक कि कोई बाद की नीति पूर्वव्यापी रूप से लागू न की जाए। ... "

19. हम यह दर्ज करते हैं कि अमित श्रीवास (उपरोक्त) में दिया गया निर्णय, उपर्युक्त उद्धृत कंडिका 16 में, पहले के एक निर्णय स्टेट ऑफ गुजरात बनाम अरविंद टी. तिवारी¹⁷ का उल्लेख इस प्रकार करता है, मानो कि ऐसा निर्णय यह कानून निर्धारित करता हो कि एक बाद की नीति पूर्वव्यापी रूप से लागू की जा सकती है। जबकि हम अरविंद टी. तिवारी (उपरोक्त) में ऐसा कोई कानून ढूँढने में असमर्थ रहे हैं, उस निर्णय की कंडिका 18 में हमें यह मिलता है:

"18. इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा यह प्रश्न तैयार किया गया था कि अनुकंपा के आधार पर रोजगार के आवेदन पर मौजूदा नियमों के अनुसार विचार किया जाना है, या कर्मचारी की मृत्यु की तारीख को विद्यमान नियमों के तहत, जिस पर विचार किए जाने की आवश्यकता नहीं है।"

यह वास्तव में बहस का विषय है कि क्या अनुकंपा नियुक्ति की नीति, जो कि एक कार्यकारी आदेश की प्रकृति की है, पूर्वव्यापी आवेदन कर सकती है।

20. यह मानते हुए भी, अमित श्रीवास (उपरोक्त) में निर्णय के तुरंत बाद, इंडियन बैंक बनाम प्रोमिला¹⁸ और स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम आशीष अवस्थी¹⁹ में दो न्यायाधीशों की समन्वय पीठों के दो निर्णय आए हैं। बाद वाले ने, अमित श्रीवास (उपरोक्त) और प्रोमिला (उपरोक्त) के निर्णयों पर विचार करते हुए, कंडिका 5 में यह मत व्यक्त किया है:

"5. इस न्यायालय द्वारा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए निर्धारित विधि के सुनिश्चित सिद्धांत के अनुसार, केवल मृत कर्मचारी की मृत्यु के समय प्रचलित नीति पर ही विचार करना आवश्यक है, न कि बाद की नीति पर।"

21. एन.सी. संतोष (उपरोक्त) और अमित श्रीवास (उपरोक्त) के निर्णय, जो कि तीन-न्यायाधीशों की पीठों द्वारा दिए गए थे, इस बात पर स्पष्ट रूप से भिन्न हैं कि अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन का निर्णय करने के लिए कौन सी नीति लागू होगी - वह नीति जो मृतक कर्मचारी की मृत्यु की तारीख को प्रचलित थी या वह जो अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पर विचार करने की तारीख को प्रचलित थी।

22. शेओ शंकर तिवारी (उपरोक्त) द्वारा किए गए संदर्भ पर अभी तक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय लिया जाना बाकी है; अतः, हमने इस जटिल मुद्दे पर सूचित और आधिकारिक निर्णय उपलब्ध कराने के लिए या, यदि आवश्यकता हो, तो तीन-न्यायाधीशों की समन्वय पीठों द्वारा व्यक्त किए गए परस्पर विरोधी विचारों और दो- न्यायाधीशों की पीठों के भिन्न-भिन्न विचारों की बड़ी संख्या को ध्यान में

रखते हुए, इसे अभी भी बड़ी पीठ को समुचित संदर्भ के लिए भेजने के लिए, बाद में दिए गए निर्णयों का उल्लेख करना उपयुक्त समझा है।

23. चूँकि **केनरा बैंक** (उपरोक्त) के मामले को एक बड़ी पीठ को संदर्भित किया गया है और बड़ी पीठ ने अभी तक अपना निर्णय नहीं दिया है, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने यह प्रस्तुत करने के लिए सुना गया कि हमें ऐसे निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हालाँकि, इस अपील पर निर्णय सुरक्षित रखे जाने के बाद से बीते हुए समय को देखते हुए, हम और अधिक देरी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी पीठ का निर्णय दिखाई नहीं दे रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिवादी दो दशकों से अधिक समय से यह नहीं जानता है कि उसका भाग्य क्या होगा, इसकी प्रतीक्षा कर रहा है।

विश्लेषण और निर्णय

24. हमने निर्णय के लिए उत्पन्न होने वाले मूल मुद्दे के साथ-साथ अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए मार्गदर्शक कानूनी सिद्धांतों पर भी विचार किया है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। जैसा कि पहले देखा गया है, मूल मुद्दे पर निर्णय के लिए हमें कुछ उप-मुद्दों का भी उत्तर देना होगा। हम इस प्रक्रिया में उनका भी उत्तर देने का प्रस्ताव करते हैं।

25. पहला उप-मुद्दा प्रतिवादी के पिता के निधन के बाद व्यतीत हुए समय से संबंधित है। दो दशक से अधिक का समय हो गया है। प्रतिवादी के अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पर अंततः निर्णय लेने में लगे समय का आकलन करने के लिए यहां किसी को भी आवर्धक लेंस लगाने की आवश्यकता नहीं है। पक्षकार दूसरे दौर में तीसरी सीढ़ी तक पहुंच चुके हैं। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक यह है कि इसे जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। जब तक कि परेशानी को कम करने की आवश्यकता उत्पन्न होने के तुरंत बाद नियुक्ति नहीं की जाती है, तब तक (i) मृतक कर्मचारी की अचानक समय से पहले और असामयिक मृत्यु या (ii) चिकित्सा अक्षमता जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी सेवा में जारी रहने के लिए अयोग्य हो जाता है, के कारण तत्काल वित्तीय संकट से निपटने की आवश्यकता जिसके लिए नियुक्ति की पेशकश करके भलाई दिखाई जाती है, मौजूद नहीं रह सकती है और इस प्रकार ऐसी नियुक्ति का मूल उद्देश्य ही विफल हो सकता है।

26. अक्सर, अनुकंपा नियुक्ति के लिए अस्वीकृत दावे काफी समय लेने के बाद उच्च न्यायालयों या यहां तक कि इस न्यायालय तक पहुंचते हैं। मुकदमेबाजी का सामान्य नियम यह है कि अनुतोष के अधिकार का निर्णय उस तारीख के संदर्भ में किया जाना चाहिए जिस दिन याचिकाकर्ता ने न्यायालय में प्रवेश किया था। कानून में याचिकाकर्ता जिस अनुतोष का हकदार है, उसे बाद की और मध्यवर्ती घटनाओं, यानी मुकदमे की शुरुआत की तारीख और निर्णय की तारीख के बीच की घटनाओं के कारण अभी भी इक्विटी (न्यायसंगतता) के आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है; हालाँकि, कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि ऐसी राहत को केवल याचिकाकर्ता की कोई गलती न होने पर न्यायिक या अर्ध-न्यायिक मंच में कार्यवाही चलाने में लगे समय के कारण अस्वीकार नहीं किया जा सकता है [देखें: **बेग राज सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**⁹⁰]। इसलिए, केवल न्यायालयों द्वारा अपने समक्ष मुद्दे का निर्णय करने में लिए गए समय के कारण किसी दावे को खारिज करना विवेकपूर्ण या बुद्धिमानी नहीं होगी।

27. समय का बीतना, तथापि, अनुकंपा नियुक्ति को अस्वीकार करने का एक प्रमुख कारक हो सकता है जहाँ दावा विलंबित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। विलंबित रूप से प्रस्तुत किए गए दावों के मामलों में यह वैध रूप से अनुमान लगाया जाता है कि मृत/अक्षम कर्मचारी का परिवार तत्काल वित्तीय सहायता की आवश्यकता में नहीं है। हालाँकि, एक उचित समय क्या होगा, यह काफी हद तक विचाराधीन अनुकंपा नियुक्ति की नीति/योजना पर निर्भर करेगा। यदि आवेदन करने के लिए कोई

समय सीमा निर्धारित की गई है और आवेदक ऐसी अवधि के भीतर आवेदन करता है, तो समय के बीतना को अस्वीकृति का आधार नहीं माना जा सकता है।

28. इस मामले में, प्रतिवादी के पिता की मृत्यु दिसंबर 2001 में हुई थी। अब, हम 2025 में हैं। प्रतिवादी को देरी के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वह लगन से अपना दावा पहले अपीलकर्ता के समक्ष और उसके बाद उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा था। इस प्रकार, प्रतिवादी की वर्तमान आयु चाहे जो भी हो, उसकी उम्र उसके दावे को समाप्त करने और गुण-दोष के आधार पर उस पर विचार करने पर रोक लगाने के लिए निर्णायक नहीं हो सकती।

29. दूसरा उप-मुद्दा अनुकंपा नियुक्ति की पेशकश करके प्राप्त किए जाने वाले वास्तविक उद्देश्य से संबंधित है। हमने 1993 की योजना के उद्देश्यों पर ध्यान दिया है और अनुकंपा नियुक्ति के लिए किसी भी दावे का निर्णय लेने हेतु ऐसे उद्देश्यों को स्वागत योग्य माना है। सेवाकाल में मृत्यु के मामलों में अनुकंपा नियुक्ति के पीछे का अंतर्निहित विचार यह प्रतीत होता है कि कर्मचारी, जो परिवार में एकमात्र कमाने वाला था, के असामयिक और अप्रत्याशित निधन से परिवार के सदस्य ऐसी दरिद्र स्थिति में आ जाते हैं कि अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के बिना, वे जीवित नहीं रह सकते। सेवाकाल में मरने वाले कर्मचारियों के सभी मामलों पर समान रूप से लागू होने वाला कोई कठोर सूत्र नहीं हो सकता जो अनुकंपा आधार पर नियुक्ति को ज़रूरी करे। प्रत्येक मामले की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं और उसे परिवार की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए निपटाने की आवश्यकता होती है। यह केवल "तंगी की स्थिति वाले" मामलों में ही है कि अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर विचार किया जाना चाहिए और, यदि अन्य सभी शर्तें संतुष्ट हों, तो उसे प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसे "तंगी की स्थिति वाले" मामलों में वे मामले शामिल होंगे जहाँ मृतक का परिवार 'गरीबी रेखा से नीचे' है और जीविका के किसी भी स्थिर स्रोत की कमी के कारण भोजन, किराया, उपयोगिताएँ, आदि जैसे बुनियादी खर्चों का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसे कमाने वाले की मृत्यु से उत्पन्न होने वाले जीवन स्तर में महज़ गिरावट से अलग समझा जाना चाहिए।

30. उपर्युक्त *कुंती तिवारी* (सुप्रा) में किया गया अवलोकन महत्वपूर्ण प्रतीत होता है और हम इससे प्रेरणा लेते हुए यह अवलोकन करते हैं कि अनुकंपा के आधार पर कोई भी नियुक्ति इस प्रकार नहीं की जानी चाहिए जैसे कि यह कोई सामान्य या अधिकार का मामला हो, इस संबंध में किसी भी नीति/योजना के प्रशंसनीय उद्देश्य से सौभाग्य से बेखबर रहते हुए।

31. इस प्रकार, यह पता लगाने के लिए वित्तीय स्थिति की जांच करना कि भरण-पोषण करने वाले की मृत्यु के कारण प्रतिवादी और उसकी माँ अत्यधिक वित्तीय संकट में थे या नहीं, ऐसी बात नहीं है जिसे हल्के में नज़रअंदाज़ किया जा सके।

32. यह हमें तीसरे उप-मुद्दे पर ले जाता है, जिसमें हमें यह विचार करने का काम सौंपा गया है कि क्या प्रतिवादी के पिता की मृत्यु के परिणामस्वरूप परिवार की वित्तीय स्थिति का उचित और तर्कसंगत मूल्यांकन किया गया है। एमडी और सीईओ के आदेश को ऊपर, *अक्षरशः* उद्धृत किया गया है। ऐसे आदेश को केवल पढ़ने से यह पता चलता है कि मृतक अपने पीछे अपनी विधवा, प्रतिवादी और तीन बेटियों को अपने जीवित उत्तराधिकारियों के रूप में छोड़ गया। सभी बेटियाँ विवाहित थीं और बसी हुई थीं। केवल उसकी पत्नी और बेटा ही आश्रित गिने जा सकते थे। यह नहीं दिखाया गया है कि बेटियाँ अपने जीवित रहते और सेवा में रहते हुए मृतक पर आश्रित थीं। प्रतिवादी और उसकी माँ अपने ही घर में रह रहे थे। इसके अलावा, मृतक अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति से 4 (चार) महीने दूर था। ऐसे आदेश में यह इंगित किया गया है कि मृतक का अंतिम शुद्ध वेतन क्या था और यदि वह अधिवर्षिता के बाद भी जीवित रहता, तो उसे मासिक पेंशन के रूप में कितनी राशि प्राप्त होती। साथ ही, प्रतिवादी की माँ को दी जा रही मासिक पारिवारिक पेंशन की राशि भी इंगित की गई है। हालाँकि, प्रतिवादी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उसकी वित्तीय स्थिति का कोई उचित मूल्यांकन नहीं

किया गया है, बल्कि अजीब बात यह है कि एमडी और सीईओ द्वारा संदर्भित आंकड़ों पर बिल्कुल भी विवाद नहीं किया गया है। इस प्रकार, हमारे पास इन आंकड़ों को सही मानकर आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यदि, वास्तव में, प्रतिवादी के पिता को 6398/-रुपये की पेंशन राशि प्राप्त होती और उन्हें अपना तथा अपने दो आश्रितों, अर्थात् अपनी पत्नी और बेटे, का भरण-पोषण करना पड़ता, तो शुरु में स्वीकृत पारिवारिक पेंशन की राशि, यानी 4637.92 रुपये, किसी भी कल्पना से, दो लोगों के भरण-पोषण के लिए अपर्याप्त या नाकाफी नहीं कही जा सकती थी। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादी/उसकी माँ को दी गई 3.09 लाख रुपये की शुद्ध सेवा समाप्ति लाभ की राशि उतनी ही होती, जितनी मृतक को अधिवर्षिता के बाद, यदि वह जीवित होता, तो सेवा समाप्ति लाभ के रूप में प्राप्त होती। इस प्रकार, यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ प्रतिवादी के पिता की मृत्यु ने ऐसा भयानक परिणाम और/या विनाशकारी नतीजा लाया हो कि प्रतिवादी और उसकी माँ को दयनीय प्रभावों का सामना करना पड़े, जिसका समाधान, जैसा कि प्रतिवादी ने आग्रह किया, केवल अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की पेशकश करके ही किया जा सकता था। हमें प्रतिवादी के विद्वान वकील से सहमत न होने पर खेद है।

33. अगला उप-मुद्दा, जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता, वह यह है। 1993 की योजना में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए दावेदार की उपयुक्तता के आकलन की परिकल्पना की गई है। जैसा कि इस न्यायालय के कई निर्णयों में, जिन्हें ऊपर नोट किया गया है, निर्धारित किया गया है, अनुकम्पा नियुक्ति की नीति/योजना का हिस्सा बनने वाले खंडों का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। प्रतिवादी को उपयुक्तता परीक्षण के अधीन किए बिना, खंडपीठ स्पष्ट रूप से **केनरा बैंक** (उपरोक्त) के निर्णय पर भरोसा करते हुए प्रतिवादी की क्लर्क श्रेणी में नियुक्ति का निर्देश देने में त्रुटि कर गई। यह कुछ महत्व की बात है कि **केनरा बैंक** (उपरोक्त) ने भी नियुक्ति का आदेश नहीं दिया था, बल्कि दावे पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता बताई थी।

34. आयु में छूट दी जानी चाहिए थी या नहीं, यह अगला उप-मुद्दा है। प्रतिवादी की ओर से एक तर्क उठाया गया था, जो सफल रहा, जिसका आशय यह था कि चूंकि वह अपने पिता की मृत्यु की तारीख पर केवल आठ महीने ही अधिक आयु का था, इसलिए उसे आयु में छूट दी जानी चाहिए थी जिसके लिए शक्ति 1993 की योजना द्वारा प्रदान की गई थी। हम जानते हैं कि प्रतिवादी की ओर से इस तर्क में दम है कि यह मुद्दा अब यहां तय करने के लिए खुला नहीं है। शुरु में लिया गया यह निर्णय कि प्रतिवादी अधिक आयु का था, मुकदमेबाजी के पहले दौर में रद्द कर दिया गया था और इसलिए, पूर्वन्याय का सिद्धांत वास्तव में आकर्षित होता है।

35. हालाँकि, इस बिंदु पर कुछ विस्तार से बहस की गई है, इसलिए 1993 की योजना की व्याख्या पर हमारे विचार भविष्य में इसी तरह के मुद्दे का निर्णय करने वाले न्यायालयों के लिए कुछ मूल्य के हो सकते हैं। हम अपीलकर्ता के विद्वान वकील से सहमत हैं कि आयु में छूट का प्रश्न तभी उठेगा जब दावेदार अनुकंपा नियुक्ति के लिए 1993 की योजना की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करता हो। जो तार्किक प्रतीत होता है वह यह है कि किसी भी आश्रित, जो अन्यथा उपयुक्तता सहित अनुकंपा नियुक्ति के सभी मानदंडों को पूरा करता है, को केवल आयु-सीमा के आधार पर बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाना चाहिए। यदि दावेदार की आयु छूट योग्य सीमा के भीतर पाई जाती है, तो उपयुक्त मामले में विवेक का प्रयोग किया जा सकता है। आयु में छूट पूरे प्रक्रिया के अंतिम चरणों में लिया जाने वाला एक कदम है और यह विचार के लिए तभी आएगा जब नियुक्ति की अन्य सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं। यदि किसी दिए गए मामले में, जैसे कि यह, यह पाया जाता है कि मृतक का परिवार निर्धन नहीं है, तो पहली सीमा पार नहीं होती है और इस प्रकार, प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती है। ऐसे मामले में, यह विचार करना एक बेकार औपचारिकता होगी कि आयु में छूट दी जानी चाहिए या नहीं।

36. अंत में, यह ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि एकल पीठ ने एमडी और सीईओ द्वारा पारित अस्वीकृति के विवादित आदेश को रद्द करने पर प्रतिवादी के दावे पर आगे विचार करने का निर्देश

दिया, खंडपीठ एक कदम और आगे बढ़ गई और नियुक्ति का निर्देश दिया। एक अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ कानूनों द्वारा सीमित होती हैं। जब तक अपील में कोई विशेष मामला प्रकृति में इतना असाधारण न हो कि अपीलीय न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 33 द्वारा अपीलीय न्यायालयों को प्रदत्त शक्ति के समान शक्ति का प्रयोग करना अनिवार्य मानता हो, ऐसी शक्ति का सामान्यतः प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। हमें उक्त प्रावधान का संदर्भ उस स्रोत के रूप में नहीं मिला जिससे खंडपीठ ने प्रतिवादी को उपयुक्तता परीक्षण के अधीन किए बिना नियुक्ति की पेशकश करने का आदेश देने की शक्ति प्राप्त की। इसलिए, यह स्पष्ट है कि अपील दायर करने के लिए अपीलकर्ताओं की स्थिति बदतर नहीं हो सकती थी।

37. मूल मुद्दे की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए, हमने पाया है कि उच्च न्यायालय — एकल पीठ और खंडपीठ दोनों ने — अपने-अपने निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए **केनरा बैंक** (उपरोक्त) के निर्णय पर अत्यधिक भरोसा किया। हम उच्च न्यायालय की दुर्दशा की सराहना करते हैं। शायद, उक्त पीठों के पास कोई और विकल्प नहीं था, सिवाय इसके कि वे इस न्यायालय ने उसमें जो कुछ भी अवलोकन किया और निर्णय लिया, उससे स्वयं को बाध्य महसूस करें; और भी इसलिए, क्योंकि वह निर्णय स्वयं अपीलकर्ता द्वारा तैयार की गई 1993 की योजना से संबंधित था, जो यहाँ विचाराधीन है।

38. उच्च न्यायालयों को, हम दोहराते हैं, इस न्यायालय के निर्णय **डायरेक्टर ऑफ सेटलमेंट्स, ए.पी. बनाम एम.आर. अप्पाराव**¹ में दिए गए फैसले को ध्यान में रखना चाहिए, जहाँ इस न्यायालय के निर्णय के बाध्यकारी प्रभाव के संबंध में कुछ प्रासंगिक टिप्पणियाँ की गई थीं। संबंधित अंश इस प्रकार है:

"7. ... अनुच्छेद 141 के तहत बाध्यकारी होने वाला कानून, इसलिए, किसी दिए गए मामले में न्यायालय द्वारा उठाए गए और निर्णित सभी बिंदुओं के अवलोकनों तक विस्तृत होगा। जहाँ तक संवैधानिक मामलों का संबंध है, यह न्यायालय की एक प्रथा है कि उन बिंदुओं पर कोई फैसला न सुनाया जाए जो सीधे उसके निर्णय के लिए नहीं उठाए गए हैं। उच्चतम न्यायालय के किसी निर्णय को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि कुछ पहलुओं पर विचार नहीं किया गया था या संबंधित प्रावधानों को न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया था (देखें ...)। जब उच्चतम न्यायालय कोई सिद्धांत निर्धारित करता है, तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पालन करना उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय का कर्तव्य होगा। उच्च न्यायालय का कोई भी निर्णय जो उच्चतम न्यायालय के निर्णय और निर्देशों का पालन करने से इनकार करता है या उच्च न्यायालय के उस निर्णय को पुनर्जीवित करने की कोशिश करता है जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था, वह शून्य है। ... "

(जोर दिया गया)

39. संविधान के अनुच्छेद 141 के मद्देनजर, **केनरा बैंक** (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय का अनुपात उच्च न्यायालय पर बाध्यकारी था, भले ही उस निर्णय में इस न्यायालय ने 1993 की योजना के सभी प्रावधानों पर विचार किया हो या न किया हो। यहाँ तक कि इस न्यायालय का अवांतर कथन भी उच्च न्यायालयों पर बाध्यकारी हो सकता था। हालाँकि, एक समन्वय पीठ होने के नाते, हम न तो किसी अवांतर कथन से, और न ही किसी ऐसे सिद्धांत से स्वयं को बाध्य महसूस करते हैं जो किसी पिछले निर्णय में स्थापित किया गया हो जिसने वित्तीय स्थिति के मुद्दे पर सभी प्रासंगिक दृष्टिकोणों से विचार करने का अवसर न लिया हो।

40. इस तथ्य को दरकिनार करते हुए कि **केनरा बैंक** (उपरोक्त) को एक बड़ी पीठ के पास भेजा गया है, हमने सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे की स्वतंत्र रूप से जाँच की है।

41. **केनरा बैंक** (उपरोक्त) के निर्णय की कंडिका 1 सिविल अपीलों में उत्पन्न होने वाले कानून के सामान्य प्रश्न को दर्ज करता है। संक्षेप में, प्रश्न यह था कि क्या 1993 की योजना के अस्तित्व के दौरान 'सेवाकाल में मृत्यु' प्राप्त करने वाले कर्मचारी के परिवार के सदस्य अनुकंपा नियुक्ति का दावा करने के हकदार थे, भले ही उनकी वित्तीय स्थिति अच्छी थी और 1993 की योजना को 2005 की योजना से बदल दिया गया था।

42. यह तर्क देते हुए कि अपीलकर्ता का पक्ष अनुचित था, समन्वय पीठ को इस न्यायालय के कई निर्णयों पर विचार करने का अवसर मिला और अंततः उसने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"19. जहाँ तक अपीलकर्ता बैंक की इस दलील का संबंध है कि चूँकि प्रतिवादी का परिवार पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है और उन्होंने सेवा समाप्ति लाभ भी प्राप्त किए हैं, तो हमारे विचार से, अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पर विचार करते समय इसका कोई परिणाम नहीं है। 1993 की योजना का खंड 3.2 कहता है कि यदि मृतक कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति की पेशकश की जानी है और वह नाबालिग है, तो बैंक नाबालिग के बालिग होने तक नियुक्ति के प्रस्ताव को खुला रख सकता है। यह इंगित करेगा कि सेवा समाप्ति लाभ प्रदान करना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि यदि सेवा समाप्ति लाभ दिया भी जाता है, यदि आवेदक नाबालिग है, तो बैंक नाबालिग के बालिग होने तक नियुक्ति को खुला रखेगा।

...

22. उस समय लागू 'डाइंग इन हार्नेस योजना 1993' के दायरे और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता बैंक को सही तरीके से यह निर्देश दिया कि वह कानून के अनुसार और उस समय मौजूद योजना के अनुसार प्रतिवादी के अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर पुनर्विचार करे। हमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है।"

43. हमारे सुविचारित मत में, 1993 की योजना के उद्देश्य और निर्धारित प्रारूपों (क्रमशः अनुलग्नक I और II) में मृतक कर्मचारी की वित्तीय स्थिति और देनदारियों के विवरण से संबंधित प्रकटीकरण की आवश्यकताएं नीति निर्माताओं के इरादे के बारे में किसी को भी संदेह में नहीं छोड़ेंगी। 1993 की योजना के मूल में आय के मुख्य स्रोत के अचानक बंद हो जाने के कारण उत्पन्न हुई तत्काल वित्तीय कठिनाइयों पर काबू पाना और आश्रितों में से किसी एक को रोजगार की आवश्यकता वाली निर्धन परिस्थितियों का अस्तित्व होना है, इसलिए इसे कानून के एक वैध प्रस्ताव के रूप में स्वीकार करना मुश्किल है, यदि असंभव नहीं, कि सेवानिवृत्ति लाभों का अनुदान किसी भी परिणाम का नहीं हो सकता, क्योंकि 1993 की योजना की कंडिका 3.2 उस समय तक नियुक्ति के प्रस्ताव को खुला रखने की अनुमति देता है जब तक कि नियुक्त होने वाला उत्तरजीवी नाबालिग आश्रित वयस्कता प्राप्त नहीं कर लेता। हमारे विचार से, कंडिका 3.2 यह परिकल्पना करता है कि, नियुक्ति को आवश्यक बनाने वाली निर्धन परिस्थितियों के बावजूद, केवल पात्र आश्रित परिवार के सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य विफल नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव ऐसे नाबालिग के लिए वयस्कता प्राप्त करने तक खुला रखा जाएगा, जिसके बाद उसे उपयुक्तता के अधीन नियुक्ति की पेशकश की जाएगी, और एक बार जब वह नियुक्ति स्वीकार कर लेता है, तो वह अन्य निर्धन परिवार के सदस्यों की देखभाल करने के लिए बाध्य होगा। हालाँकि कंडिका 3.2 तत्काल वित्तीय कठिनाइयों पर काबू पाने के उद्देश्य से पूरी तरह से तालमेल में नहीं हो सकती है, इसे एक परोपकारी खंड के रूप

में देखा जाना चाहिए जो मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए, स्पष्ट रूप से असाधारण मामलों को कवर करने हेतु, उचित सीमा से परे भी अनुकंपा नियुक्ति का लाभ प्रदान करती है। 1993 की योजना में इस खंड को शामिल करने के विचार को सेवानिवृत्ति लाभों के अनुदान/रिलीज़ के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता है। दोनों अलग-अलग क्षेत्रों में संचालित होते हैं, और इसलिए, हम **केनरा बैंक** (उपरोक्त) की कंडिका 19 में दिए गए तर्क से विनम्रतापूर्वक असहमत हैं।

44. जैसा कि **बी. किशोर** (उपरोक्त) में प्रासंगिक रूप से निर्धारित किया गया है, दिवंगत कर्मचारी के आश्रितों की निर्धनता अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की किसी भी योजना के तहत पूरी की जाने वाली मूलभूत शर्त है, और यदि ऐसी निर्धनता सिद्ध नहीं होती है, तो संरक्षणात्मक विभेद को बढ़ावा देने वाली राहत प्रदान करने से सेवाकाल में मृत कर्मचारी के आश्रितों के लिए एक प्रकार का आरक्षण उत्पन्न होगा, जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत गारंटीकृत समानता के आदर्श से सीधे टकराव होगा। इसके अलावा, न्यायिक निर्णयों की बहुतायत है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के दावे का निर्णय करते समय, मृत कर्मचारी के परिवार की वित्तीय स्थिति का आकलन किया जाना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में, योजना का उद्देश्य कमजोर हो सकता है; इस मूल्यांकन के बिना, सेवा में रहते हुए मरने वाले कर्मचारी का कोई भी आश्रित रोजगार के अधिकार का दावा कर सकता है, मानो यह विरासत में मिलने वाला अधिकार हो।

45. इन सभी निर्णयों के निर्णय के आधार को, सेवाकाल के दौरान मृत कर्मचारी के वास्तव में जरूरतमंद आश्रितों को सहायता प्रदान करने के नेक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सद्भाव में पढ़ा जाना चाहिए, न कि उन्हें एक पद के बदले दूसरा पद देने के उद्देश्य से। इस संबंध में **उमेश कुमार नागपाल** (उपरोक्त) में दी गई चेतावनी को याद रखना होगा कि मृतक के निराश्रित परिवार के विपरीत, लाखों अन्य परिवार हैं जो, यदि अधिक नहीं तो, उतने ही निराश्रित हैं।

46. हमारे उपरोक्त तर्क के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एमडी और सीईओ का वह आदेश जिसमें प्रतिवादी के अनुकंपा नियुक्ति के प्रार्थना को अस्वीकार किया गया था, अद्वितीय था और इसलिए, रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग में किसी भी हस्तक्षेप के लिए उत्तरदायी नहीं है।

47. उसी समय, हम **केनरा बैंक** (उपरोक्त) के निर्णय से अनभिज्ञ नहीं हो सकते, जिसे एक समकक्ष पीठ द्वारा दिया गया है। **केनरा बैंक** (उपरोक्त) से असहमति रखते हुए, न्यायिक औचित्य यह मांग करता है कि हम उचित मार्ग का अनुसरण करें, यानी, मामले को एक बड़ी पीठ को संदर्भित करें। हम इस कानूनी स्थिति से भी अनभिज्ञ नहीं हैं कि जब तक जिस निर्णय पर संदेह किया जाता है वह अतिष्ठित नहीं हो जाता, तब तक वह बाध्यकारी बना रहता है। **शियो शंकर तिवारी** (उपरोक्त) में समकक्ष पीठ द्वारा किए गए संदर्भ के समान, यदि हमारे द्वारा संदर्भ किया जाता है, तो यह प्रतिवादी की पीड़ा और दर्द को ही बढ़ाएगा, यह देखते हुए कि विवाद के आसन्न समाधान की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, क्योंकि यह स्वीकार किया गया तथ्य है कि **शियो शंकर तिवारी** (उपरोक्त) द्वारा 2019 में किया गया संदर्भ अभी भी अनुत्तरित है।

निष्कर्ष

48. उच्च न्यायालय के सामने आई दुविधा की उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम आक्षेपित आदेश को पूरी तरह से अनुचित नहीं मान सकते हैं। जिस हद तक इसने **केनरा बैंक** (उपरोक्त) पर भरोसा किया है, उस हद तक हम खंडपीठ को, या यहाँ तक कि एकल पीठ को भी दोष नहीं दे सकते हैं। खंडपीठ, **केनरा बैंक** (उपरोक्त) से बाध्य महसूस करते हुए, एमडी और सीईओ के आदेश की उचित जाँच करने का अवसर नहीं पा सकी। उसका स्पष्ट मत था कि उक्त आदेश इस न्यायालय द्वारा **केनरा बैंक** (उपरोक्त) की कंडिका 19 में दिए गए निर्णय के विपरीत था। हालाँकि, उसी समय, हम इस दृढ़ मत के हैं कि **केनरा बैंक** (उपरोक्त) के बावजूद, खंडपीठ को उत्तरदाता की सीधी नियुक्ति का

निर्देश देते समय उपयुक्तता से संबंधित मानदंड को अनदेखा नहीं करना चाहिए था। इस हद तक, अपीलकर्ता के विद्वान वकील सही हैं कि उपयुक्तता का प्रश्न **केनरा बैंक** (उपरोक्त) द्वारा अछूता छोड़ दिया गया था और अपीलकर्ता को उसकी अपील पर एक ऐसा आदेश भुगतने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए था जिसके रिट याचिका पर दिए गए आदेश की तुलना में अधिक प्रतिकूल परिणाम हों।

49. मामले की उपयुक्तता में, हमने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का आह्वान करने का निर्णय लिया है। इस अपील पर विचार कर रही एक अन्य समकक्ष पीठ ने 21 मई, 2024 को यह अवलोकन किया था कि वह पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए उत्तरवादी को एक एकमुश्त राशि के भुगतान का निर्देश देने पर विचार करेगी और, तदनुसार, पक्षों को निर्देश प्राप्त करने के लिए समय दिया गया था। हालाँकि कोई समझौता नहीं हुआ और क्या प्रतिवादी एकमुश्त अनुग्रह राशि के लिए 2005 की योजना के अंतर्गत आता है, इसकी जाँच न तो हमने और न ही उच्च न्यायालय ने की है, लेकिन समकक्ष पीठ के दृष्टिकोण के साथ-साथ उच्च न्यायालय के समक्ष उसकी सफलता के आधार पर उत्तरवादी के मन में नियुक्ति की आशा उत्पन्न होने की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, हम संतुष्ट हैं कि न्याय के हित की पर्याप्त रूप से पूर्ति होगी यदि अपीलकर्ता को आज की तारीख से 2 (दो) महीने की अवधि के भीतर उत्तरवादी को ₹2.5 लाख का एकमुश्त भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है और कार्यवाही को बंद कर दिया जाता है। तदनुसार, यह आदेश दिया जाता है। हम तुरंत यह भी जोड़ना चाहेंगे कि यह राशि ₹50,000/- के अतिरिक्त होगी जो उत्तरवादी को नोटिस जारी करते समय एक अन्य समकक्ष पीठ के पिछले आदेश के अनुसार भुगतान किया गया था।

50. अंतिम विश्लेषण में, खंडपीठ के साथ-साथ एकल पीठ का आक्षेपित निर्णय और आदेश अपास्त किया जाता है।

51. उपर्युक्त शर्तों पर सिविल अपील स्वीकार की जाती है। कोई लागत नहीं।

मामले का परिणाम: अपील स्वीकार की गई।

[†] शीर्ष टिप्पणियाँ तैयार की गयीं: द्वारा विभूति भूषण बोस

* लेखक

(प्रतीक राय द्वारा अनुवादित)

- 1 अपीलकर्ता
- 2 आक्षेपित आदेश
- 3 उच्च न्यायालय
- 4 उत्तरवादी
- 5 1993 की योजना
- 6 डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 38363/2003 (पी)।
- 7 2005 की योजना
- 8 (2015) 7 एससीसी 412
- 9 (2007) 4 एससीसी 778
- 10 एमडी और सीईओ
- 11 डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 16592/2016
- 12 डब्ल्यूए 1364/2016
- 13 (1997) 8 एससीसी 85
- 14 (2008) 8 एससीसी 475
- 15 (2002) 10 एससीसी 246
- 16 (2008) 13 एससीसी 730
- 17 (1989) 4 एससीसी 468
- 18 (2009) 11 एससीसी 453
- 19 (2008) 15 एससीसी 560
- 20 (2009) 13 एससीसी 600
- 21 (2011) 4 एससीसी 209
- 22 (2021) 20 एससीसी 695
- 23 (2009) 13 एससीसी 112
- 24 (1994) 4 एससीसी 138
- 25 (2011) 13 एससीसी 131
- 26 (2007) 6 एससीसी 162
- 27 (2012) 9 एससीसी 545
- 28 (2000) 7 एससीसी 192
- 29 (2007) 2 एससीसी 481
- 30 (1998) 5 एससीसी 452
- 31 (2004) 7 एससीसी 271
- 32 (2012) 11 एससीसी 307
- 33 (2006) 7 एससीसी 350
- 34 (2004) 12 एससीसी 487
- 35 (2004) 7 एससीसी 265
- 36 (2000) 6 एससीसी 493
- 37 (2019) 3 एससीसी 653
- 38 (1994) 2 एससीसी 718
- 39 (2007) 9 एससीसी 571
- 40 (2007) 8 एससीसी 148
- 41 (2006) 12 एससीसी 44
- 42 (2010) 11 एससीसी 661
- 43 (2014) 13 एससीसी 583
- 44 (2019) 5 एससीसी 600
- 45 (2020) 7 एससीसी 617
- 46 (2020) 10 एससीसी 496
- 47 (2012) 9 एससीसी 545
- 48 (2020) 2 एससीसी 729
- 49 (2022) 2 एससीसी 157
- 50 (2003) 1 एससीसी 726
- 51 (2002) 4 एससीसी 638